[श्री मनीराम बागड़ी]

फिर, 1983 में यह कर बढ़ कर 115% तकरीबन हो गया और अब 1984 में फिर यह बढ़ कर 119 परसेंट हो गया है। कार्क हल्का माल है। इसके कच्चे माल की जो कीमत है उससे ज्यादा जहाज का किराया है। एक टन माल की कीमत 150 डालर है तथा जहाज का किराया 210 डालर है। इस प्रकार माल 360 डालर का हो जाता है। इसके ऊपर 119 परसेंट कर लगता है।

जबसे ऊपर लिखे कर बढ़ते गए हैं, इंडस्ट्री की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गयी है। 18 महीने से कार्क फैक्टरी वाले सरकार से मांग कर रहे हैं कि कच्चे माल के ऊपर कर हटाकर उनको बचाया जाए परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1983 में जून के महीने में एक डेलिगेशन फाइनेन्स मिनिस्ट्री से मिला परन्तु अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। लगभग दस कंपनियां बंद हो गई हैं तथा बाकी भी बहुत जल्दी बन्द होने वाली हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि कर नीति बदलें। कच्चे माल पर आधा कर दिया जाए। देश में यह पहली वस्तु है कि जिसके कच्चे तथा बने हुए माल पर एक ही कर है। अगर इस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो सारी कार्क की फैक्टरीयां बंद हो जायेंगी। हजारों आदमी बेकार हो जायेंगे तथा उसके बाद सारा बना माल विदेश से मंगवाना पड़ेगा जिससे देश को करोड़ों रु० का फारेन एक्सचेंज का नुकसान होगा और देश आगे की बजाय पीछे जायेगा।

(vi) Need for inquiry into alleged irregularities in Rohilkhand University

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में स्थित रूहेलखंड विश्वविद्यालय की कोरी डिग्रियां बाजार में खुलेआम एक हजार रुपये में बिक रही हैं। विश्वविद्यालय के छपे अंक पत्र भी बाजार में बेचे जा रहे हैं। बी० काम० की डिग्री नं० 20915 तथा बी० ए० की डिग्री नं० 37158 मुझे भी प्राप्त हुई हैं। जनता में इस बात से अत्यन्त रोष व्याप्त है कि विश्वविद्यालय का कार्यालय अनुत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से काम कर के विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने में लगा हुआ है। इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घोर अनियमितताओं, पक्षपात से संबंधित अ कों शिकायतें बरेली के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने समय-समय पर भी की हैं। परन्तु कोई कार्यवाही न होने से जनता व छात्रों में अत्यंत असंतोष व्याप्त हो गया है। इस गंभीर प्रकरण पर तुरन्त कठोर कार्यवाही करने के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(vii) Postponement of Third All India Conference of Urban Cooperative Banks and Cooperative Societies fixed for March 9 and 10, 1984, and inconvenience to delegates because of their not having been informed in time about the change in dates

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अरबन कोआपरेटिव बैंक्स और कोआपरेटिव सोसायटीज का तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में दिनांक 9 तथा दस मार्च, 1984 को होना निश्चित हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन कृषि तथा सहकारिता मंत्री, राव बीरेन्द्र सिंह को करना था। रिजर्व बैंक के गवर्नर भी सम्मेलन को सम्बोधित करने वाले थे।

किन्तु जब सम्मेलन में भाग लेने वाले हजारों प्रतिनिधि, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे सुदूर प्रदेशों से आये थे, 8 मार्च को सम्मेलन के स्थल एशियाड ग्राम पहुंचे तो वहां सम्मेलन का नामोनिशान भी नहीं था। प्रतिनिधियों का स्वागत करना तो दूर, वहां यह बताने वाला भी कोई नहीं था कि सम्मेलन कहां होगा और प्रतिनिधियों के ठहरने की क्या व्यवस्था की गई है। एशियाड ग्राम में प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे 24, अकबर रोड जायें। वहां पहुंचने पर प्रतिनिधियों को पता चला कि सम्मेलन का 24, अकबर रोड से कोई संबंध नहीं है। बाद में प्रतिनिधियों को पता चला कि सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। प्रतिनिधियों को वापस जाने में भी उन्हें भारी कठिनाई हुई, क्योंकि रेलवे से अपना आरक्षण उन्होंने इस सम्मेलन की पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार कराया था।

मेरा कृषि मंत्री से आग्रह है कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दे कर सारी स्थिति स्पष्ट करें और बतायें कि सम्मेलन की तिथियां क्यों परिवर्तित की गई, तिथि परिवर्तन की सूचना समय पर प्रतिनिधियों को क्यों नहीं दी गई और यहां से प्रतिनिधियों के आने जाने का व्यय कौन उठाएगा?

(viii) Need for steps for minimising the suffering of farmers affected by Rengali Multi-purpose Dam project in Khaira C.D. Block (Balasore) Distt.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Sir the Rengali multi-purpose dam project has displaced 10,000 families from 265 villages in the Sambalpur and Dhenkana districts of Orissa. Located in the Talcher sub-division, the project is designed to control floods in the vast low-lying areas of the river valley and utilise the river water for power generation and irrigation. The resettlement programme envisages the allotment of land for cultivation and housing, the displaced families will also get forest products at concessional rates for house-building and cash compensation besides being provided with community wells, schools, clubs, villages roads and dispensaries.

But this massive programme to evacuate and resettle the villagers which is in progress since 1976 has not gained momentum yet. All the 61 resettlement colonies envisaged to be brought under rural electrification programme remain a distant dream.

Similarly vast stretch of cultivable land acquired by the state administration in 1960's in Khaira C.D. block of Balasore district to bring under cultivation by Salandi left canal scheme remains a day dream for the people of the area. People had lost their valuable lands and the State administration on their part had dug trial pits for canal purposes and if the canal is not feasible for any reason, the lands acquired should have been returned to the affected farmers who are willing to repay back the amounts received from the Government.

Hence, I urge upon the Government at the Centre to advise the state in this regard so that the farmers' sufferings are minimised.

14.32 hrs.

GENERAL BUDGET, 1984-85
GENERAL DISCUSSION-
Contd.

MR. CHAIRMAN : Now, we will take up further General Discussion on the Budget (General) for the year 1984-85. Shri Sunil Maitra was already on his legs. He has already taken 1 hour 4 minutes as against 54 minutes allotted to his Party. I would request him to conclude his speech.